(v) The Agreement was initially for a period of five years. Thereafter, the Agreement is automatically renewable from year to year unless a notice for termination of the Agreement or request for a new Agreement in writing is given by either side three months prior to the expiration of the Agreement.

(c) India's imports from Iran during the last three years were as follows:—

Year	Value of Imports (Rs. in crores)
1993-94	1190.44
1994-95	1684.59
1995-96	1968.88

The main commodities imported from Iran were crude oil, organic/inorganic chemicals, pig iron, fruits & nuts, sulphur & unroasted iron pyrites, metallic ores and metal scrap, pulses, etc.

ग्रेनाइट की खोज के लिए एकक

*165. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ग्रेनाइट की खोज करने और उसके संसाधित करने हेतु एकक स्थापित किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की है और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों से कोई सर्वेण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (घ) ग्रेनाइट के गौण खनिज होने के कारण खनिज रियायतों की मंजूरी का अधिकार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकारों के पास निहित हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार राज्य के ग्रेनाइट भण्डार केवल मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (राज्य सरकार का उपक्रम) को ही दिए जाते हैं जो एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा राज्य में संयुक्त क्षेत्र में ग्रेनाइट गवेषण और पालिशिंग यूनिटों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तदनुसार, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बस्तर जिले के कोंटा तहसील के मुला, किसौली क्षेत्र में पाए गए ग्रेनाइट के विदोहन के लिए जनवरी, 1996 में मैसर्स पैसिफिक इंडस्ट्रीज, उदयपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः मध्य प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ग्रेनाइट भण्डारों का सर्वेक्षण विशेषरूप से इसके विदोहन और शोधन को ध्यान में रखते हुए अभी तक आरम्भ नहीं किया है।

केन्द्रीय विकलांग आयोग

*166. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक केन्द्रीय विकलांग आयोग का गठन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या इस आयोग में विकलांगों को सदस्य के रूप में नामित करने का कोई प्रावधान है;

(घ) इस आयोग का गठन क्या होगा:

(ङ) **क्या** सरकार ने विकलांगों के खेल और मनोरंजन हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Changes in Present Public Distribution System

*167. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state: